News Broadcasting & Digital Standards Authority
Order No. 119 (2021)

Order of NBDSA (formerly known as NBSA) on complaint dated 20/30.4.2021 by Mr. Matin Rafiuddin Mujawar against Zee News regarding a programme aired on 13.4.2021

Complaint 20/30.4.2021:

The complaint relates to a news programme titled "*Taal Thok Ke LIVE: 'गला काट कट्टरता' से आजादी कब? | AIMIM Kanpur Kattarta Poster | Wasim Rizvi | TTK*" which was broadcast on 13.4.2021 on Zee News.

Zee न्यूज़ ने कानपुर में लगे AMIM के सर तन से जुदा वाले पोस्टर के विषय को लेकर "*इस्लाम और मुस्लिम समाज पर निशाना थामा. है* " इस पोस्टर पर स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती और वासिम रिज़वी की तस्वीर छपी थी. सनातनी मानसिकता वाले धर्मांद स्वामी नरसिंहानंद के खिलाफ देश भर में मुस्लिम समाज रास्ते पर उतरा है. इन्होने पैगंबर मुहंमद और इस्लाम के प्रति जहर उगला था. स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रेस कॉनफेरेन्स में मुसलमानो के पैग़ंबर मोहम्मद और वासिम रिजवी ने कुरान के खिलाफ अपमानित करने वाले और असामाजिक भाषा का इस्तेमाल किया था. जिस के कारण देश भर में इन के विरोध में लोग रास्ते पर उत्तर कर प्रदशन कर रहे है इन दोनों अपराधियों ने मुस्लिम समाज के मजहबी भावनाओ को चोट पहुचायी थी और इस्लाम मजहब को अपमानित किया था. इन दोनों अपराधियों के खिलाफ देश भर में कई FIR दर्ज हुए है. देश के सब से बड़ी न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर अपराध के लिए वासिम रिजवी को ५०,००० जुर्माना किया था.

Zee न्यूज़ अपने समाचार माध्यम का हमेशा से गलत इस्तेमाल करता आया है. "ताल ठोक के" जैसे खबरों के माध्यम से मुस्लिम और इस्लाम विरोधी भाषा करने वाले ऐसे कट्टर अपराधियों के असांविधानिक तत्वों की हिमायत Zee न्यूज़ लगातार कर रहा है.

Zee न्यूज़ देश में हिन्दू मुस्लिम दंगा, और देश में भीषण हिंसा को फ़ैलाने के हेतु से लगातार ऐसे कार्यकर्म करता आया है. ऐसे कार्यक्रम में बुलाये गए पैनलिस्ट हिन्दू तथा कट्टर संघटन से जुड़े होते है जो असामजिक तत्व, हिंसा, नफरत और राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुचाने वाले भाषा का इस्तेमाल करते आया है.

Zee न्यूज़ के खिलाफ NBSA में इस से पहले कई शिकयते दर्ज है ऐसे होते हुए भी असामाजिक तत्वों को फैलाने वाले खबरों का सिलसिला Zee न्यूज़ ने जारी रखा है. Zee न्यूज़ कानून, संविधान और NBSA के नियमो को बार बार अपने पैरो तले रौंदता आया है.

Zee न्यूज़ ने AIMIM जैसे किसी एक पार्टी या व्यक्ति के गलत पोस्टर लगाने पर इस्लाम और शरिया को निशाना किया है. गुन्हेगार और पार्टी का कोई मजहब नहीं होता। Zee न्यूज़ का ये कृत्या असांविधानिक और कानूनी सजा के काबिल है.

भारत देश संविधान से चलता है शरिया से नहीं, ना ही भगवत गीता, कुरान, या बाइबल से. हर धर्म की अपनी किताबे है और जीवन बिताने के तरीके है. जैसे हिन्दू हिन्दुइस्म को फॉलो करते है, ख्रिस्ती लोग क्रिस्चेनिस्म, वैसे ही मुस्लिम लोग

शरीयत को फॉलो करते है. पर देश के कानून का सवाल आता है तो सब लोग संविधान और भारतीय न्याय व्यवस्था को फॉलो करते है.

इस्लाम धर्म में शरिया याने जीवन बिताने का तरीका। इस्लाम में शरिया बहोत महत्वपूर्ण है जीवन से लेकर मृत्य तक शादी, रोजा, नमाज, जकात धर्म के अनुसार बिताना इसे शरिया कहते है. Zee न्यूज़ ने अपने खबरों द्वारा इस्लाम और देश में रहने वाले मुस्लिम समाज को कट्टरता से जोड़ कर, शरिया इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करके इस्लाम मजहब के छबि को ख़राब किया है. इस तरह देश की नजरो में मुस्लिम समाज को अपराधी के कटघरे में खड़ा किया है और लगातार ऐसा प्रयास करता आया है..

खबरों की हेडलाइंस भड़काऊ, मन में क्रोध और हिंसा को उत्तेजित करने वाले है मुसलमानो के प्रति नफरत फ़ैलाने वाली तथा बरगलने वाली है

"मुँह में संविधान दिल में कत्ले आम;'
देश संविधान से चलेगा या शरिया से;गला काट कट्टरता से आजादी कब;

हिंदुस्तान में तालिबानी फतवे क्यों (मुस्लिम समाज के भीड़ पर हेडलाइंस);' आप के मुँह पे सविधान है दिल में आप के कत्ले आम; कट्टरपंथ का कमलेश मॉडल कब तक"

Zee न्यूज़ ने सीधे *"मुँह में सविधान दिल में कत्ले आम, मतलब हम तो यह ही सवाल पूछेंगे के सविधान सविधान चिल्लायेंगे गला काट कट्टरता फयलायेंगे ?"कोई धर्म नहीं सिखाता गला काट कट्टरता, फिर कानपुर में सर तन से जुदा वाले पोस्टर्स क्यों वो भी इस्लाम के नाम पर लिखा गया है "गुस्ताके रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा" हिंदुस्तान में ये ISIS वाली गला काट कट्टरता कहा से आगयी ???देश सविधान से चलेगा या शरिया से"* इस किसम के बरगलाने वाले, नफरत फ़ैलाने वाले और समाजो में दूरिया बनाने वाले भाषा का प्रयोग करके मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर उसके खिलाफ हिंसक वातावरण बनाया है.

अमन चोपड़ा मौलाना कादरी से बार बार ये साबित करने की कोशी कर रहा था के *"अगर धार्मिक भावनाये आहात होती है. इस्लाम इजाजत देता है गला काटने की ?'* इस वाक्य को लेकर लगातार इस्लाम और मुस्लिम समाज को बदनाम और देश वासियो के नजरो में गुन्हेगार के कटघरे में खड़ा करने की साजिश करता रहा है. इस तरह मुसलमानो पर और इस्लाम मजहब पर डिबेट चलाया गया है.

Zee न्यूज़ ने समाचार माध्यम से बार बार मुसलमनो को गला काट कट्टरता ISIS कह कर बदनाम किया है. मुँह में सविधान दिल में कत्ले आम, मतलब हम तो यह ही सवाल पूछेंगे के सविधान सविधान चिल्लायेंगे गाला काट कट्टरता फयलायेंगे ?

सविधान के वजह से हाथ बंधे है, वर्ना इस्लाम इजाजत देता है गला काटने की धार्मिक भावनाए आहात होने पर. मुझे क्लैरीफिकेशन चाहिए, मुझे नहीं पता है. इस तरह के सवाल मौलाना कादरी से राष्ट्रीय न्यूज़ माध्यम पर करके अमन चोपड़ा ने मुस्लिम समाज की छबि को खराब करने का प्रयास किया है. इस तरह के सवालों का विपरीत परिणाम दर्शको के मानसिकता पर निश्चित हुआ हैआप इसी लिए गला कॉटने जा रहे है ताकि हिन्दू राष्ट्रना बने. कमलेश तिवारी का इस लिए गाला काटा था. अमन चोपड़ा के ये वाक्य देश का हिन्दू मुस्लिम ऐसा बटवारा करने वाले और देश को हिंसक स्तिथि में झोकने वाले है

मौलाना कादरी अमन चोपड़ा को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे तब अमन चोपड़ा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसके पेठ से असलियत बाहर आने लगी जिस पर भारतीय मुसलमानो पर यह कह कर अमन चोपड़ा ने आरोप लगाए *" आप बोल नहीं सकते इस चीज को क्यों के आप लोगों के मुँह पर सविधान होता है और दिल में तालिबान होता है."* ऐसे बेबुनियाद नफरत फ़ैलाने वाले वाक्यों से देश में रहने वाले मुस्लिम समाज को निशाना बनाया है.

विनोद बंसल ने जेहादी सोच, ये इस्लाम का ग्लोबल प्रास्पेक्टिव बन रहा है ये टिपणी की. इस्लाम का नाम आते ही लोग खड़े हो जाते है. जगह जगह उनको शक की नजर से देखा जाता है. इस तरह इस्लाम के छबि को ख़राब करने वाली भाषा का प्रयोग किया . विनोद बंसल विश्व हिन्दू परिषद् के नेता है जो इस्लाम विरोधी संघटन है । ऐसे संघटन के प्रवक्तो द्वारा Zee न्यूज़ इस्लाम के विरोध में देश में तनाव और अशांति फ़ैला रहा है

स्वय सुप्रीम कोर्ट ने पवित्र कुरान का सम्मान करते हुए वासिम रिजवी के पेटिशन को गलत और बेबुनियाद साबित करके खारिज किया था. सुप्रीम कोर्ट ने वासिम रिजवी पर ५०,००० रूपये का जुर्माना भी लगाया था. ऐसे होते हुए भी Zee न्यूज़ के साहयता से संगीत रागी ने कुरान के बारे में कलकत्ता पिटीशन और १९८६ के पोस्टर का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट का अवमान किया है। कुरान के प्रति नफरत फ़ैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल प्रसार माध्यम से करके पवित्र कुरान और उसके आस्था का अपमान किया है.

"अगर गुस्ताके रसूल की सजा गाला काटना होता तो सब से पहले रसूल के इंतकाल के बाद आप ने उनकी खिलाफत के विरासत के लड़ाई में बॉडी को अठारा घंटे तक सड़ाया था तो सब से पहले गाला काटते हजरत अली, जब आप ने रसूल के बेटी को बीबी फ़तिमाह को भरी महफ़िल में जलील किया था" इस तरह सुबुही खान ने हजरत महंमद और बीबी फातिमा का अपमान कर के इस्लाम मजहब के पवित्रता को चोट पहुंचाई. सुबुही खान के इन वाक्यों ने बहोत बड़ा हंगामा खड़ा किया क्यों के सुबोहि खान द्वारा इस्तेमाल किये गए शब्द पैगम्बर और उनके बेटी फातिमा के प्रतिमा को अपमानित करने वाले थे.

इस वक्त ऐसे कार्यक्रम द्वारा मुस्लिम विरोध में जहर घोलने वाले अमन चोपड़ा को यह कहना पड़ा के हम कार्यक्रम द्वारा डिस्क्लेमर चलाते है के इस प्रोग्राम में जो विश्लेषकों की राय है वो उनकी अपनी निजी राय है इस में Zee न्यूज़ का कोई भी संबंध नहीं है.

अमन चोपड़ा ने कानून को और देश के सुव्यवस्था को खुले आम चुनौती दी है और हमेशा से देता आया है. अमन चोपड़ा ने देश के जनता को बरगलाया है. Zee न्यूज़ की भाषा और ऐसे न्यूज़ मुस्लिम समाज के विरोध में जनप्रकोप को उत्तेजित करने वाली है. न्यूज़ एंकर अमन चोपड़ा ने करोडो लोगों के सामजिक भावनाओ को चोट पहोचाई है. NBSA के नियमो का उलंघन करके Zee न्यूज़ बार बार चुनवती दे रहा है. इस के खिलाफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैण्डर्ड अथॉरिटी के दफ्तर में भी कही शिकायते दर्ज है. देश में होने वाले हर सांप्रदायिक हिंसा को इस तरह के खबरे जिम्मेदार है. Zee न्यूज़ आये दिन प्रसार माध्यम का गलत इस्तेमाल करके देश में

हिंसक स्तिथि निर्माण करने के तैयारी में है. Zee न्यूज़ किसी पोलिटिकल पार्टी का या कट्टर हिंदुत्त्ववादी संघटन से प्रेरित है। स्वय Zee न्यूज़ की खबरे इस बात का साबुत पेश करती है.

Zee न्यूज़ की खबरे राष्ट्रीय एकात्मता और अखंडता के हित में घातक और नुक्सान पहुंचानेवाली साबित हो रही है. Zee न्यूज़ देश को हिंसा के तरफ ले जाने की कोशिस कर रहा है.Zee न्यूज़ ने सांप्रदायिक इरादों से भारतीय मुस्लिम समाज तथा उनके मौलिक और मानवाधिकारों को लक्षित किया है. मुस्लिम समाज की मानहानि करके उसे निचा दिखाया है. Zee न्यूज़ प्रसार माद्यम भड़काऊ खबरों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा निर्माण कर रहा है. देश के विरुद्ध युध्द पुकारने के बराबर अपराध है.

Letter of apology dated 1.5.2021

विषय : दुबारा आवेदन/नोटिस का स्वीकार किया जाए.

मुँह पर सवविधान दिल में कत्ले आम, गला काट कट्टरता से आजादी कब ? April 13, 2021 को ZEE न्यूज़ द्वारा प्रसारित हुए इस विषय को लेकर २० अप्रैल २०२१ को ZEE न्यूज़ के दफ्तर में हम ने आवेदन/नोटिस ईमेल किया था. गलती से मेल के साथ जोड़ा हुआ आवेदन ये गलत और आधाअधूरा होने का ज्ञान हुआ है. इस लिये दुबारा आवेदन की कॉपी मेल कर रहा हु. इस आवेदन की कॉपी ZEE न्यूज़ को भी मेल की गयी है

आवेदन के गलत होने का ज्ञान सेकंड लेवल कंप्लेंट के समय हुआ है. इस गलती का अफ़सोस है इस लिए माफ़ी नामा लिख रहा हु.

ZEE न्यूज़ द्वारा प्रसारित हुआ यह विषय संवेदनशील है इस लिए इस विषय पर NBSA द्वारा कानूनी कार्रवाई होना बहोत ही जरुरी और महत्वपूर्ण है. इस लिए गलती को माफ़ किया जाए और नजरअंदाज किया जाए और दुबारा मेल किये गये नोटिस/आवेदन को अंतिम समज कर ZEE न्यूज़ को इस बारे में सूचित किया जाए. इस गलती को लेकर NBSA के दफ्तर में माफीनामा दायर कर रहे है.

Complaint dated 13.5.2021 filed with NBSA:

The complainant stated that he was escalating the complaint since he had not received a response from the broadcaster. That the broadcaster has no respect for the law and the rules framed by NBSA. He stated that the contents of the broadcast were communally flavoured and that the broadcaster was continuously airing series of provocative news targeting the minorities of India with communal intention and to cause damage to National Integration.

Decision of NBSA on 28.5.2021

NBSA considered the complaint, letter of apology and viewed the footage of the broadcast. NBSA noted that since the initial complaint dated 20.4.2021 was filed by the complainant within the time stipulated under NBSA Regulations, it would consider the complaint. NBSA decided to call the complainant and the broadcaster for a hearing at the next meeting and directed the broadcaster to submit its response to the complaint.

Response from the Broadcaster:
The broadcaster in its reply dated 30.5.2021 stated that the complainant had in his complaint dated 20.04.2021, raised various false, misleading, frivolous and motivated allegations against the contents of the programme '*Taal Thok Ke*' aired on Zee News on 13.4.2021. The broadcaster stated that in the impugned programme, it had fairly and objectively conducted a debate/panel discussion on the issue of putting up of poster, allegedly by AIMIM, in Kanpur, Uttar Pradesh calling for the beheading of Yati Narsinghanand and former Chairman of Central Shia Waqf Board, Mr. Wasim Rizwi, against which the Kanpur Police had registered an FIR on 12.04.2021 under Sections 153A and 295 of Indian Penal Code.

At the outset, the broadcaster denied each and every allegations, averments and insinuations levelled in the complaint, as the same were completely false, frivolous, unfounded and misleading. Before dealing with the allegations levelled in the complaint, the broadcaster stated that the complaint was not maintainable, inasmuch as, the same was hopelessly barred by limitation. That under Rule 8.1.6 of the NBSA Regulations "*a complaint shall be made to the broadcaster by a person aggrieved within a reasonable time not exceeding 7 (seven) days from the date of first broadcast.*" In the present case, the broadcaster stated that the impugned programme was first broadcast on 13.04.2021 and as such, the limitation to file a complaint against the impugned broadcast expired on 20.04.2021. However, the present complaint had been submitted with the broadcaster on 30.04.2021 i.e. after a delay of about 10 days and no explanation/reasons for the said delay had been furnished by the complainant in his complaint. The broadcaster submitted that since the complaint was hopelessly barred by limitation it was liable to be dismissed.

Further, it stated that the present complaint was not maintainable in as much as, the impugned programme did not violate any of the Guidelines and Code of Ethics framed by the News Broadcasters Association and the Hon'ble NBSA. That the impugned programme was completely neutral, objective and impartial and as such, the complaint was nothing but another malicious attempt on the part of the complainant to muzzle the voice of a responsible media from reporting the truthful account of important facts and events and discussion thereon. That the complaint was not in consonance with the NBSA Regulations and as such, was liable to be dismissed.

That the allegations levelled in the complaint were completely baseless and motivated and the contents of the impugned programme were neither intended to outrage the religious feelings of any particular community or religion nor intended to disturb the communal harmony, as falsely alleged. The broadcaster stated that as a responsible media house of the country, it has the utmost respect for the Constitution of India and its values and as such, treats all the religions, class,

communities alike and telecasts news reports without any flavour of biasness and partiality. Therefore, the allegation that in the impugned programme it had intended to provoke religious tension, was completely false and baseless.

The broadcaster stated that it has always been raising its strong voice against the religious extremism and intolerance leading to public disorder and harmony and in the impugned programme, it had only objected to the conduct of the extremists people who put a poster calling for the beheading of Yati Narsinghanand and Mr. Wasim Rizwi for allegedly making adverse remarks on Islam. Thus, by way of the impugned programme, it had not hurt the religious sentiments or targeted any religious group as falsely alleged by the complainant. It stated that its objective was only to highlight the aforesaid instances and expose those extremist elements, who in the name of religion, are trying to divide the country on communal lines.

In light of the aforesaid incident, the broadcaster stated that it had in the impugned programme reported and conducted an objective, neutral and fair panel discussion on the issue of religious extremism. That as a responsible media house it had during the impugned programme deprecated the act of putting of the aforesaid objectionable poster, in a democratic country like India, which is governed by the rule of law. The intent and objective of the aforesaid debate was to expose those few handful of extremist elements, who in the name of Islam, are spreading hate and inciting people and it had never intended to target any particular religion, which was also evident from the fact that the anchor, at the beginning of the show itself, clarified that no religion teaches violence and further stated that no one had a right to hurt the religious feelings of any community. Before initiating the debate, the anchor also categorically stated that Islam is a peaceful and tolerant religion, which does not permit such kind of criminal activities and extremism. In view of the aforesaid, the broadcaster stated that it was clear that the anchor, hosting the programme, never intended to insult or spread hate against any particular religion, as falsely alleged. That it was conducted in due compliance of the journalistic norms, applicable code of conduct and the relevant guidelines issued by the Hon'ble Authority.

The broadcaster stated that it was also pertinent to mention that since the impugned programme was a live debate and was not a pre-scripted programme, it had during the programme, repeatedly run a disclaimer on the screen, in a the form of a ticker, clearly stating that "*the views expressed by the panelists on the show are their personal views and Zee News has nothing to do with the views/ comments made by the panelist and the panelist will personally be liable for the comments made by them during the show*." The Disclaimer further stated that "*Zee News does not intend to hurt the sentiments of anyone*". In view of the aforesaid disclaimer, the broadcaster stated that the channel had neither endorsed nor can it be made liable for the statements/comments made by any of the panellists. That its reporting was completely uncolored from any motive, prejudice or notions

and was completely based on verified, accurate and established facts and did not tend to promote disharmony or enmity between the different religion.

The broadcaster stated that it had imposed self-restraint while conducting the analysis in the impugned programme and had also strictly adhered to the principles of neutrality, impartiality and fairness in the news report. In view of the above, the broadcaster stated that the since the complainant had failed to establish any deviations, the complaint ought to be dismissed at the outset.

Rejoinder dated 10.06.2021 from the Complainant:
The complainant stated that the broadcaster had disrespected the law and the impugned news appeared to be broadcaster's communally hatched agenda. He reiterated that the contents of the programme appeared to be pre-planned agenda for targeting minorities. The broadcaster has intentionally intended to causing danger and harm to the life and democratic rights of minorities as well as to disturb the communal harmony of the state. That the broadcaster was frequently targeting minority by airing such provocative news. The broadcaster was attempting to create communal unrest in the country which needed to be stopped with penalty and strict legal action and cancellation of the license to broadcast of news. Further, he stated that even anchor of the impugned news programme was required to be banned from the Indian news media with a criminal case.

Hence the complainant stated that it had also previously filed complaints against the broadcaster and the anchor for allegedly using racist language to spread rumours and disharmony.

The complainant requested for NBSA to personally look in the subject news to know and understand the level of thick skinned intentions of the broadcaster who was very smartly carrying out a well planned attack against Islam, Muslims and Minorities of the country through its series of news.

The broadcaster has labelled the Indian Muslims as terrorist by stating that it was the real picture behind their hidden faces. That even the panellist invited on the show are also influenced by the ideology of the broadcaster and have left not a single space to target Islam.

The effects of broadcasting of such communally flavored news by the media houses across India has caused to hate against Minorities, communalism, destruction of property, incidents of rioting, vandalism, and arson during the protests across the country.

On being served with notice, the following were present at the hearing on 24.9.2021:

Complainant:
Mr. Matin Rafiuddin Mujawar
Adv. Ashish Kachave, Advocate

Broadcaster:
Ms. Ritwika Nanda, Advocate
Mr. Piyush Choudhary, Compliance Officer NBDSA & Senior Manager, Legal
Ms. Annie, Assistant Manager, Legal

Submissions of the Complainant:
The complainant submitted that in the impugned programme, the broadcaster had while reporting on the "*Sar tan se juda*" poster allegedly put up by AIMIM in Kanpur, Uttar Pradesh targeted Islam and the Muslim community in particular. That in the programme, the broadcaster used inflammatory and provocative headlines and taglines such as "मुँह में संविधान दिल में कत्ले आम"; "देश संविधान से चलेगा या शरिया से" ; "गला काट कट्टरता से आजादी कब"; "हिंदुस्तान में तालिबानी फतवे क्यों" (मुस्लिम समाज के भीड़ पर हेडलाइंस); and "कट्टरपंथ का कमलेश मॉडल कब तक" to incite violence, spread hatred against the Muslim community and cause communal disharmony in the country.

Further, during the programme the anchor made following provocative statements "कोई धर्म नहीं सिखाता गला काट कट्टरता, फिर कानपुर में सर तन से जुदा वाले पोस्टर्स क्यों वो भी इस्लाम के नाम पर लिखा गया है "गुस्ताके रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा" हिंदुस्तान में ये ISIS वाली गला काट कट्टरता कहा से आगयी ??? देश सविधान से चलेगा या शरिया से" ; **"**अगर धार्मिक भावनाये आहात होती है.**" "**इस्लाम इजाजत देता है गला काटने की**?"** "सविधान के वजह से हाथ बंधे है, वर्ना इस्लाम इजाजत देता है गला काटने की धार्मिक भावनाए आहात होने पर. मुझे क्लैरीफिकेशन चाहिए, मुझे नहीं पता है." ; "आप इसी लिए गला कॉटने जा रहे है ताकि हिन्दू राष्ट्रनाबने. कमलेश तिवारी का इस लिए गाला काटा था.**";** " आप बोल नहीं सकते इस चीज को क्यों के आप लोगों के मुँह पर सविधान होता है और दिल में तालिबान होता है." to disturb communal harmony in the country and outrage the religious feelings of a community. Further during the impugned programme, one of the panellists even insulted the Islam religion.

The complainant submitted that on 12.4.2021, the Kanpur unit of AIMIM had allegedly put up incendiary 'sar tan se juda' posters, calling for the beheading of Dasna Devi Temple head priest Yati Narsinghanand Saraswati and Wasim Rizvi for his remarks on Prophet Muhammad. That the Kanpur Police had taken cognizance of the poster and registered an FIR against an unknown person and efforts are still being made to identify the accused. However, in the impugned programme, the broadcaster presented Mr. Narsinganand Saraswati and Mr. Wasim Rizvi who have a criminal background as a hero and defamed a specific community deliberately. The anchor repeatedly blamed Islam for the controversial poster which was put up by an unknown person.

The complainant submitted that while the posters were indeed condemnable, however the language used by the anchor in the programme was equally unacceptable. That the broadcaster has been habitually running programmes that have a communal agenda and a tendency to disturb the communal harmony in the country.

Submissions of the Broadcaster:
The broadcaster submitted that the subject of the impugned programme was a hoarding on which it was categorically written at top AIMIM, in Kanpur, Uttar Pradesh and which called for the beheading of Yati Narsinghanand and former Chairman of Central Shia Waqf Board, Mr. Wasim Rizwi. It was categorically stated in the hoarding that such people should be beheaded. The broadcaster submitted that the Kanpur Police had already registered an FIR on 12.04.2021 against the poster/hoarding.

It submitted that in the impugned programme, it had fairly and objectively conducted a debate/panel discussion on the issue of putting the poster with panellists Mr. Sangeet Ragi (Professor, Delhi University), Vinod Bansal (Spokesperson, Vishwa Hindu Parishad), Subuhi Khan (Social Woker), Abdul Razzak Khan (Political Analyst) and Syed Asim Waqar (Spokesperson AIMIM) and Maulana Ali Qadri.

The broadcaster submitted that the common theme in all the programmes by which the complainant was aggrieved was that they opposed extremism and did not give a communal colour as alleged by the complainant. The broadcaster submitted that it has always been raising its strong voice against religious extremism and intolerance and in the impugned programme, it had only objected to the conduct of the extremist's people. Further, even the panellists during the impugned programme stated that in India public calls for beheading a person cannot be made.

That from the complaint it appears that the complainant has knit picked certain remarks made by the panellists. That on viewing the programme as a whole it would be clear that panellists have expressed their various views on whether this form of extremism should be condemned or not and unfortunately it was the complainant who instead of condemning such reprehensible acts was giving a communal colour to the programme. The broadcaster reiterated that it had run a balanced discussion with a fairly representative panel which included even the spokesperson of AIMIM.

Decision
NBDSA looked into the complaint, response from the broadcaster, and also gave due consideration to the arguments of both the complainant and the broadcaster and reviewed the footage.

NBDSA found no specific violation of the Code of Ethics and Broadcasting Standards or Guidelines in the broadcast and decided that no action was called for on the complaint.

NBDSA decided to close the complaint with the above observations and inform the complainant and the broadcaster accordingly.

NBDSA directs NBDA to send:
(a) A copy of this Order to the complainant and the broadcaster;
(b) Circulate this Order to all Members, Editors & Legal Heads of NBDA;
(c) Host this Order on its website and include it in its next Annual Report and
(d) Release the Order to media.

It is clarified that any statement made by the parties in the proceedings before NBDSA while responding to the complaint and putting forth their view points, and any finding or observation by NBDSA in regard to the broadcasts, in its proceedings or in this Order, are only in the context of an examination as to whether there are any violations of any broadcasting standards and guidelines. They are not intended to be 'admissions' by the broadcaster, nor intended to be 'findings' by NBDSA in regard to any civil/criminal liability.

Sd/-

Justice A.K Sikri (Retd.)
Chairperson

Place: New Delhi
Date : 19.11.2021